बिहार सरकार
मुख्यमंत्री का कार्यालय
(जनसंपर्क कोषांग)
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–**cm-86**
11/02/2025

मुख्यमंत्री ने औरंगाबाद जिले में चल रही विकासात्मक योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की

- समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने की कई महत्वपूर्ण घोषणायें

पटना, 11 फरवरी 2025 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज प्रगति यात्रा के क्रम में औरंगाबाद जिले में चल रही विकासात्मक योजनाओं के संबंध में समाहणालय स्थित योजना भवन सभागार में समीक्षात्मक बैठक की।

समीक्षात्मक बैठक में औरंगाबाद के जिलाधिकारी श्री श्रीकांत शास्त्री ने जिले में चल रही विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति का प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी। जिलाधिकारी ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, हर घर नल का जल एवं उनका अनुरक्षण, हर घर तक पक्की गली–नाली, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, हर खेत तक सिंचाई का पानी, कृषि फीडर का निर्माण, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत कनेक्शन योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य उपकेंद्र में टेलीमेडिसीन के माध्यम से चिकित्सा परामर्श, पशु चिकित्सा सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी एवं पंचायत सरकार भवन के निर्माण की अद्यतन स्थिति के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। इसके अलावा हर पंचायत में 10+2 विद्यालय, ग्राम पंचायत/नगर पंचायत में खेल–कूद को बढ़ावा देने हेतु स्पोर्ट्स क्लब का गठन, प्रत्येक पंचायत में खेल का मैदान, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष), मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों का गठन, राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता, दाखिल खारिज/परिमार्जन/परिमार्जन प्लस एवं जल–जीवन–हरियाली के तहत जीर्णोद्धार कराए गए सार्वजनिक कुओं, पोखर तथा तालाबों की अद्यतन स्थिति के संबंध में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष औरंगाबाद जिले के जनप्रतिनिधियों ने अपने–अपने क्षेत्र की समस्याएं भी रखीं।

समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आप सभी का इस बैठक में अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। औरंगाबाद के जिलाधिकारी श्री श्रीकांत शास्त्री ने जिले में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति एवं अद्यतन स्थिति से हम सभी को अवगत कराया है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। यहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी–अपनी बातें रखी हैं। जिन्हें अधिकारियो ने नोट किया है। मैं यही चाहूंगा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा समस्याओं के संबंध में जो जानकारी यहां दी गई है, उस पर संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। आज हमने औरंगाबाद जिले में कई जगहों पर जाकर विकास कार्यों को देखा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 नवंबर, 2005 को भाजपा के साथ मिलकर हमलोगों ने बिहार के विकास के लिए काम करना शुरू किया, तब से निरंतर हमलोग बिहार को आगे बढ़ाने में लगे हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही हमें मुख्यमंत्री बनवाया। वर्ष 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी, आप सभी इससे अवगत हैं। शाम के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डरते थे। हिन्दू–मुस्लिम के बीच प्रायः झगड़े होते थे, जिसे हमने खत्म कराया। अस्पतालों में इलाज का इंतजाम नहीं था, सड़कें जर्जर थीं। शिक्षा की हालत ठीक नहीं थी।

अस्पतालों में मरीजों को दवा नहीं मिलती थी। बिजली आपूर्ति की स्थिति दयनीय थी। देहाती इलाकों की बात तो छोड़ दीजिए, राजधानी पटना में भी प्रतिदिन अधिकतम 8 घंटे से अधिक बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती थी। जब बिहार के लोगों ने हमलोगों को काम करने का मौका दिया, तब से बिहार की स्थिति बदली है। हर क्षेत्र में विकास के काम किए जा रहे हैं। हमलोग सभी पार्टी के जनप्रतिनिधियों की जरूरी मांगों पर आवश्यक कार्रवाई करते हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। जब हम सांसद थे तो सड़कों के अभाव में क्षेत्र में काफी पैदल ही चलना पड़ता था। जो भी सड़कें थी वो भी जर्जर थीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2006 से हमलोगों ने कब्रिस्तानों की घेराबंदी का काम शुरू कराया। अब तक 8 हजार से अधिक कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा दी गई है, 1273 और कब्रिस्तानों को चिह्नित किया गया है, जिसमें से 746 कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा दी गई है और शेष बचे कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई जा रही है। हमलोगों ने देखा कि मंदिरों से मूर्ति चोरी की घटनाएं हो रही हैं, इसे देखते हुए 60 वर्ष से अधिक पुराने मंदिरों की चहारदीवारी के निर्माण का निर्णय लिया गया ताकि मंदिरों में चोरी की घटनाएं न हो। हमलोगों ने कोई काम नहीं छोड़ा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमलोगों ने काफी कराया है। बड़ी संख्या में स्कूल भवनों का निर्माण कराया गया। नियोजित शिक्षकों को बड़े पैमाने पर बहाली की गई। वर्ष 2006 से सरकारी विद्यालयों में पढ़नेवाले बच्चों के लिए पोशाक योजना की शुरुआत की गई। वर्ष 2009 से लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू की गई थी लेकिन जब लड़कों ने मांग शुरू की तो वर्ष 2010 से उनके लिए भी साइकिल योजना शुरू की गई। लड़कियों को जब साइकिल दी गई तो वे समय पर स्कूल जाने लगीं। इसके साथ ही लड़कियां शाम में अपने माता–पिता को बाजार भी ले जाती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे बिहार में विकास का काम हमलोग करा रहे हैं। बिहार का कोई भी इलाका विकास से अछूता नहीं है। हमलोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल–पुलिया के निर्माण का काम बड़े पैमाने पर कराया है, जिसके कारण बिहार के किसी भी कोने से पहले 6 घंटे में लोग पटना पहुंचते थे, अब उसे घटाकर 5 घंटे किया गया है। इसके लिए हर प्रकार से काम किया जा रहा है। बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षकों की बहाली की जा रही है। इसके साथ ही नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के माध्यम से सरकारी मान्यता प्रदान की जा रही है। हमलोगों ने मदरसों को भी सरकारी मान्यता प्रदान की है और वहां पढ़ानेवाले शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के अनुरूप वेतन दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी सुधार कराया गया है। वर्ष 2005 से पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक माह में सिर्फ 39 मरीज इलाज कराने आते थे। हमलोगों ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा एवं इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई, जिसके कारण अब एक माह में औसतन 11 हजार से अधिक मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने पहुंच रहे हैं। पहले बिहार में सिर्फ 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। बिहार का सबसे पुराना अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पी०एम०सी०एच०) को 5400 बेड की क्षमता का बनाया जा रहा है। इतने अधिक क्षमता का मेडिकल कॉलेज एंड हास्पिटल दुनिया में कहीं नहीं है। बाकी 5 पुराने मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों का भी विस्तार कर 2500 बेड की क्षमता का अस्पताल बनाया जा रहा है। आई०जी०आई०एम०एस०, पटना का भी विस्तार कर उसे 3000 बेड की क्षमता का अस्पताल बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने वर्ष 2015 से सात निश्चय योजना के माध्यम से हर घर तक नल का जल, हर घर में शौचालय का निर्माण, हर घर तक पक्की गली नाली का निर्माण, हर टोले तक पक्की सड़क का निर्माण, हर घर तक बिजली का कनेक्शन जैसी मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुंचा दी है। जो भी नई बसावटें बनी हैं, उनमें भी ये सुविधाएं

उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिन लोगों के घरों में शौचालय निर्माण के लिए जगह नहीं थी, वैसे परिवारों के लिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया। वर्ष 2020 से सात निश्चय योजना–2 के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, टेलीमेडिसीन, बाल हृदय योजना, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमलोगों ने महिला सशक्तिकरण पर भी काफी बल दिया। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या काफी कम थी। जब हमलोगों की सरकार बिहार में बनी तो हमलोगों ने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर स्वयं सहायता समूह की संख्या को बढ़ाया। बिहार में अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 10 लाख 61 हजार हो गई है जिनसे 1 करोड़ 35 लाख जीविका दीदियां जुड़ी हैं। स्वयं सहायता समूह का नाम 'जीविका' एवं इससे जुड़ी महिलाओं का नाम 'जीविका दीदी' हमलोगों ने ही दिया है, जिससे प्रेरित होकर उस समय की केंद्र सरकार ने भी इसे अपनाया और इसका नाम आजीविका किया। हमलोगों ने अब बिहार के शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन शुरू कराया है। अब तक शहरी इलाकों में 34 हजार स्वयं सहायता समूह का गठन हो चुका है जिनसे 3 लाख 60 हजार जीविका दीदियां जुड़ चुकी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2006 से पंचायती राज संस्थाओं तथा वर्ष 2007 से नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। अब तक कुल 4 चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं चुनकर आई हैं। हमलोगों ने वर्ष 2013 से पुलिस की बहाली में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया, जिसका नतीजा है कि बिहार पुलिस बल में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। बिहार पुलिस में जितनी महिलाएं हैं, देश के किसी भी अन्य दूसरे राज्य के पुलिस बल में उतनी नहीं है। वर्ष 2016 से हमलोगों ने सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 में सात निश्चय योजना–2 के तहत 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे बढ़ाकर अब 12 लाख किया गया है। अब तक 9 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दे दी गई है। इसके अलावा 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब तक 24 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा चुका है। वर्ष 2025 में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी तथा 34 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करा दिया जाएगा। हमलोगों ने सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम किया है। हमने सभी पार्टियों के साथ बैठक कर बिहार में जाति आधारित गणना कराई, जिसमें 94 लाख गरीब परिवारों को चिह्नित किया गया है, जो हर जाति से जुड़े हैं। ऐसे गरीब परिवारों को प्रति परिवार 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है ताकि वे अपना जीविकोपार्जन कर सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि औरंगाबाद जिले में सभी क्षेत्र में विकास के काम कराए गए हैं। यहां इंजीनियरिंग कॉलेज, पारा मेडिकल संस्थान और छात्रावासों का निर्माण कराया गया है। साथ ही राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला आई०टी०आई०, सभी अनुमंडलों में आई०टी०आई०, जी०एन०एम० संस्थान एवं अनेक सड़क तथा पुल–पुलियों का निर्माण कराया गया है। आवासीय विद्यालय, छात्रावास का भी निर्माण कराया गया है। हमलोगों ने तय किया है कि यहां मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा, इसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है, जिसे हमने आज जाकर देखा है। औरंगाबाद जिले में 1503 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है। अब तक 59 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य इस साल के जून माह तक पूरा करा दिया जाएगा। विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में भी काफी सुधार लाया गया है। औरंगाबाद जिले में 6 विद्युत ग्रीड सब स्टेशन तथा 38 पावर सब स्टेशन का निर्माण कराया गया है। कृषि कार्य हेतु 60 डेडीकेटेड कृषि फीडर स्थापित हो चुका है, जिसके माध्यम से 5226 किसानों को पटवन हेतु बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु यहां नवीनगर थर्मल पावर प्लांट का निर्माण कराया गया है। औरंगाबाद

जिले में अब तक 24134 जीविका स्वयं सहायता समूह का गठन हो चुका है, जिससे 3 लाख 1 हजार जीविका दीदियां जुड़ी हैं। यहां 3 जीविका दीदी की रसोई भी संचालित है।

औरंगाबाद जिले में लोगों की मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण घोषणायें

- देव नगर पंचायत में रिंग रोड का निर्माण किया जायेगा। इसके निर्माण से देव नगर पंचायत में अवस्थित ऐतिहासिक सूर्य मंदिर तक श्रद्धालुओं का आवागमन सुगम होगा साथ ही इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्र का भी विकास होगा।
- बिशुनपुर कैनाल का निर्माण किया जायेगा। पूर्व में यह कैनाल क्रियाशील थी किन्तु एन०टी०पी०सी० नवीनगर के अधिष्ठापन के बाद यह बंद हो गयी, जिससे इस क्षेत्र के किसानों को सिंचाई में काफी समस्या हो रही है, इससे लगभग 15 गांवों की 2500 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिल पायेगी।
- राष्ट्रीय उच्च पथ पर ट्रॉमा सेन्टर का निर्माण किया जायेगा। इस जिले से एन0एच0–19, एन0एच0–139 गुजरता है। साथ ही, कोलकाता–वाराणसी एक्सप्रेस–वे भी निर्माणाधीन है। यहाँ प्रतिदिन 25 से 30 सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं किन्तु गया से कैमूर के बीच एक भी ट्रॉमा सेन्टर अवस्थित नहीं है। ट्रॉमा सेन्टर के निर्माण से सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों को ससमय ईलाज की सुविधा मिल पायेगी।
- औरंगाबाद शहर में अदरी नदी पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का कार्य किया जायेगा। शहर के बीच से गुजरने वाली इस नदी के एक तरफ सड़क निर्माण कार्य तथा दूसरी तरफ पार्क विकसित कराये जाने से यह पथ शहर के लिए बाईपास का कार्य करेगा तथा पार्क विकसित होने से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- मदनपुर प्रखंड के चाँद बिगहा ग्राम में केशहर नदी पर चेकडैम का निर्माण किया जायेगा, इससे किसानों को सिंचाई में सुविधा होगी।
- नगर पंचायत, देव में अवस्थित सूर्य मंदिर के समीप सूर्य कुण्ड एवं रूद्र कुण्ड परिसर से एस०एच०–101 तक ग्रीनफील्ड सम्पर्क पथ का निर्माण किया जायेगा, इससे लोगों को आवागमन में सुविधा होगी एवं श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी। छठ पूजा के दौरान जाम की समस्या में काफी कमी आयेगी।
- औरंगाबाद जिले में मदनपुर, औरंगाबाद, नवीनगर, हसपुरा, गोह, ओबरा एवं दाउदनगर कुल 07 प्रखंडों में नये प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- औरंगाबाद जिले में स्पोर्टस कॉम्पलेक्स एवं स्टेडियम का निर्माण कराया जायेगा, इससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा।
- रफीगंज के लिए बाइपास का निर्माण कराया जायेगा।
- जम्होर पंचायत यदि नगर पंचायत बनने की शर्तों को पूरा करती है तो उसे नगर पंचायत बनाने की कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी।
- औरंगाबाद में यदि केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव आता है तो इसके लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध करायी जायेगी।
- औरंगाबाद जिले में नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बनाया जायेगा, इसके लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के लिए एक टीम को कल ही भेजा जा रहा है ताकि मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना शीघ्र हो सके। इससे लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि औरंगाबाद जिले के विकास के लिए जो भी आवश्यकता होगी, उसे पूरा किया जाएगा। विकास कार्यों से संबंधित जो भी घोषणाएं यहां की गई है, उसे जल्द

ही कैबिनेट से स्वीकृति प्रदान की जाएगी। हमलोगों का काम करने में भरोसा है, जबकि कुछ लोग इधर–उधर करने में लगे रहते हैं। केंद्र सरकार से भी भरपूर सहयोग मिल रहा है।

समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने हरित पौधा और प्रतीक चिह्न भेंटकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने औरंगाबाद जिले में कराये गये विकास कार्यों की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका 'उत्थान' का विमोचन किया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, लघु जल संसाधन मंत्री सह औरंगाबाद जिला के प्रभारी मंत्री श्री संतोष कुमार सुमन, विधायक श्री आनंद शंकर सिंह, विधायक श्री राजेश कुमार, विधान पार्षद श्री दिलीप कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष श्री अशोक कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा, जिला परिषद् की अध्यक्ष श्रीमती प्रमिला देवी, नगर परिषद अध्यक्ष श्री उदय कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, विकास आयुक्त श्री प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक श्री विनय कुमार, विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, मगध प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक श्री क्षत्रनील सिंह, जिलाधिकारी श्री श्रीकांत शास्त्री, पुलिस अधीक्षक श्री अम्बरीश राहुल सहित अन्य वरीय अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

******